हुनर ▶ झारखंड पर आईआईएचएमआर विवि की रिसर्च रिपोर्ट जारी

काबिल युवाओं के मामले में झारखंड दूसरे स्थान पर

संवाददाता

रांची : इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च विश्वविद्यालय जयपुर के स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट डीन डॉ गौतम साधु ने अपने अध्ययन रिपोर्ट में कहा कि भारत कौशल रिपोर्ट के अनुसार 26 से 29 साल के बीच की उम्र के रोजगार के काबिल उम्मीदवारों के मामले में झारखंड दूसरे स्थान पर है। जबकि 18 से 21 वर्ष की उम्र के रोजगार काबिल युवाओं के मामले में 10वें स्थान पर है। इन्हीं कारणों से झारखंड में ग्रामीण प्रबंधन पेशवरों के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2022 तक झारखंड को 165 करोड़ मैन पावर की जरुरत पड़ेगी।

श्री साधु शुक्रवार को होटल रेडिशन ब्लू में आयोजित प्रेसवार्ता में बोल रहे थे। मौके पर एनएसएस के क्षेत्रीय निदेशक दीपक कुमार मौजूद थे। श्री साधु ने कहा कि झारखंड मैन पावर का हब बन सकता है। इन युवाओं को स्कील करने की जरुरत है। ग्रामीण मैनेजमेंट की अधिक आवश्यकता है। काम पर रखने के मामले में झारखंड शीर्ष 10 नियोक्ता पंसदीदा स्थानों में से एक है।

- 18 से 21 साल के बीच में काबिल युवा में झारखंड 10वें स्थान पर

झारखंड में पेयजल आपूर्ति व स्वच्छता की गंभीर चुनौती

उन्होंने कहा कि झारखंड में जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता की गंभीर चुनौती है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में फ्लोराइड युक्त प्रदूषित पानी की आपूर्ति की जाती है, इसलिए प्रदेश में एक बेहतर जल और स्वच्छता की सुविधा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आदिवासी विकास योजना 2013 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 85 प्रतिशत लोग खुले शौच में करते है और केवल 7.6 प्रतिशत ग्रामीण घरों में शौचालय तथा 2 प्रतिशत घरों में जल निकासी की सुविधा है। राज्य में ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं का कवरेज भी बहुत कम है और आज भी 49 प्रतिशत लोग हैंडपंप पर ही निर्भर है। इस पर सरकार को फोकस करने की जरुरत है।

रांची में 3-4 साल रेन हॉवेर्स्टि लगाने की पड़ेगी जरुरत

श्री साधु ने बताया कि रांची में लगातार पानी का दोहन हो रहा है। आने वाले तीन से चार सालों के बाद हर घर में रैन हॉवेस्टिक लगाने की जरुरत पड़ेगी। पहाड़ी क्षेत्र में बारिश के पानी को रोकने की आवश्यकता है। इस पर सरकार को अधिक काम करने की आवश्यकता है। इस अभियान में आम जनता को जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में किसी क्षेत्र में 200 एमएम बारिश भी होती है, तो इस पानी को सही प्रबंधन कर उपयोग में लाया जा सकता है।

सीएसआर फंड के उपयोग में झारखंड पीछे

श्री साधु ने कहा कि सीएसआर फंड के उपयोग में झारखंड पीछे है। देश में पांच राज्य में सीएसआर फंड का उपयोग पर्यावरण, स्वच्छता अभियान, ग्रामीण विकास, स्कील डेवपलमेंट आदि के कार्यो में उपयोग हो रहा है। देश में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में सीएसआर फंड का उपयोग कई प्रोजेक्ट में किये जा रहे हैं। झारखंड में केंद्र व राज्य सरकार और सीएसआर फंड के माध्यम से पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में 7040 करोड सीएसआर फंड में जमा है। इनमें 250 कंपनियां सीएसआर के तहत काम कर रही है। झारखंड में सीएसआर फंड को बढ़ाने की जरुरत है। इस पर प्रयास करना होगा। देश में 21 प्रतिशत सीएसआर फंड का उपयोग नही हो पा रहा है।

झारखंड में ग्रामीण प्रबंधकों की आवश्यकता बढ़ी : डा. गौतम

रांची : आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय जयपुर के डीन डा. गौतम साधु ने कहा कि झारखंड में ग्रामीण प्रबंधकों की आवश्यकता बढ़ी है। एनएसडीसी -2015 की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि 2022 तक झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए 1.65 करोड़ की आवश्यकता है। आज यहां आयोजित प्रेसवार्त्ता में उन्होंने बताया कि काम पर रखने के मामले में झारखंड शीर्ष 10 नियोक्ता पसंदीदा स्थानों में से एक है जबकि रोजगार के काबिल जनसंख्या के मामले में 9वें स्थान पर है। 26-29 साल के उम्र के रोजगार के काबिल उम्मीदवारों में झारखंड दूसरे पायदान पर है। उन्होंने कहा कि राज्य में ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाओं का कवरेज काफी कम है।

छाया : फिरोज

2.12 lakh tribals facing water, sanitation issues in State

PNS ■ RANCHI

Empowering the tribes through various schemes has been one of the primary focuses in the state of Jharkhand. However, there are indeed various other segments which need more focus and the manpower for the social well-being of the tribal people.

This fuelling the growing need of Rural Mangers in the state of Jharkhand, IIHMR University, Jaipur shared its insights over a press conference on Saturday. As per its findings, more than 2.12 lakh tribal people in the state are still grappling with water and sanitation problems.

"The state needs an improved water and sanitation facility where Flouride and Iron contamination along with poor water quality is the major issue in most parts of the state. Also, the coverage of rural water supply and sanitation services is very low in the state," stated Goutam Sadhu, Dean School of Rural Management at the varsity.

He further added, "The projected workforce by 2022 in Jharkhand is 172 lakhs and the the state needs to skill 5.8 lakh persons to meet the demand of skilled manpower. The incremental deficit of manpower in skilled and semi-skilled category is about 3.24 lakhs, which can be met by skilling the excess manpower in the minimally skilled category."

सिटी गेस्ट

कुछ बदली बदली नजर आ रही रांची

डॉ गौतम साधु, डीन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च विवि, जयपुर

रांची से मेरा लगाव बचपन से ही है। पिता एचईसी में काम करते थे। स्कूली शिक्षा, इंटर और पीजी मैंने रांची से किया। रांची छोड़े करीब ढाई दशक से ऊपर हो गए। अभी जयपुर में रह रहा हूं। यहां आना-जाना लगा रहता है। पांच साल के बाद रांची आया हूं। झारखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है। लड़कियां आगे निकल रही हैं। यहां के लोग दिल से अच्छे हैं। उनमें सेवा भाव भी है। यहां की आधारभूत संरचना में काफी बदलाव नजर आ रहा है। सड़कें चौड़ी हो गई हैं। मौसम भी काफी बदल गया है। पहले अप्रैल में ऐसी गर्मी नहीं पड़ती थी। थोड़ी गर्मी अधिक होने पर बारिश हो जाती थी। पानी की समस्या भी रांची में बढ़ गई है।

आवाज

झारखंड में पेयजल आपूर्ति व स्वच्छता की गंभीर चुनौती

रांची । राजस्थान के जयपुर स्थित आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय ने अपने अध्ययन रिपोर्ट में बताया गया है कि झारखंड में जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता की गंभीर चुनौती है। विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट के डीन डॉ. गौतम साधु ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राज्य के ज्यादातर हिस्सों में फ्लोराइड युक्त प्रदूषित पानी की आपूर्ति की जाती है,इसलिए प्रदेश में एक बेहतर जल और स्वच्छता की सुविधा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आदिवासी विकास योजना 2013 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 85 प्रतिशत लोग खुले शौच में करते है और केवल 7.6 प्रतिशत ग्रामीण घरों में शौचालय तथा 2 प्रतिशत घरों में जल निकासी की सुविधा है। उन्होंने बताया कि राज्य में ग्रमीण जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं का क्वरेज भी बहुत कम है और आज भी 49 प्रतिशत लोग हैंडपंप पर ही निर्भर है, उन्होंने बताया कि प्रदेश में शिशु मृत्यु दर भी देश में बहुत उंची है और 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के मामले में यह आंकड़ा 69 प्रति हजार है, 10 में से 4 महिलाएं कुपोषित हैं और भारत के औसम 49.7 प्रतिशत के आगे बच्चों के टीकाकरण का प्रतिशत 34.2 है।

राज्य में वर्षा का प्रबंध जरुरी : गौतम साधु

रांची: आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय, जयपुर के स्कूल ऑफ रुरल मैनेजमेंट के डीन डॉ.गौतम साधु ने झारखंड व बिहार राज्य की बुनियादी सुविधाओं को लेकर गहन सर्वे व शोध किया गया। उन्होंने कहा कि यहां 85 प्रतिशत लोग खुले शौच,7.8 प्रतिषत लोग के पास ही शौच है। ड्रेनेस व सिवरेज की समस्याएं आम बात है, 10 में से 4 प्रतिशत महिलाएं कुपोषित है।
टीकाकरण मात्र 34.2 प्रतिशत ही हो पाता है। 80 प्रतिशत बिमारियां जल के कारण होता है। पानी में फ्लोराइड, आयरन व आर्सेनिक की मात्रा पाये जा रहे है। यह बिडम्बना चौकाने वाले ही नहीं आने वाले खतरे की ओर इशारे करते है। कृषि में 80 प्रतिषत पानी सिंचाई में चला जाता है। 2 प्रतिशत पानी ही पेय जल का काम आता है। इसलिए हमें वर्षा के जल का संरक्षण जरुरी है। वर्षा जल ही जीवन, जमीन व जीवों के लिए अमृत है। इसे बेकार होने से रोकना होगा। यह काम सिर्फ सरकार के भरोसे संभव नहीं हैं बल्कि जन जागरुकता से ही संभव है। आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय, जयपुर अपने यहां इन बातों के उचित व्यवस्था के लिए प्रबंधन का एमबीए कोर्स करा रहा है। इस कोर्स को करने में 5 लाख 3 हजार 3 सौ रु.तक खर्च किस्तों में लिये जाते है। लेकिन सीआरएस फंड मिलने के कारण 3 लाख 3 हजार 3 सौ रु.तक खर्च छात्रों से लिया जाता है। दो वर्षो में ये कोर्स समाप्त कराये जाते है। यूजीसी से इस यूनिवर्सिटी की मन्यता प्राप्त है। पूरे एशिया महादेश में आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय, जयपुर का नाम है। अगस्त से क्लास चालू हो जाएगा। 14 जून से 7 जुलाई तक नामांकन की प्रक्रियाएं चलेगें। मौके पर आईआईएचएमआर विष्वविद्यालय, जयपुर की ओर से दीपक कुमार भी उपस्थित थे।

झारखंड में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काफी संभावनाएं

संवाददाता

रांची : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च यूनिवर्सिटी (जयपुर, राजस्थान) के स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट के डीन डॉ. गौतम साधु ने कहा कि झारखंड में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में छात्रों के पास काफी कुछ करने को है। एनएसडीसी के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 तक राज्य को 1.65 करोड़ कार्यबल की जरूरत है। राज्य की स्थिति ग्रामीण प्रबंधकों के लिए बेहतर और अधिक अवसर पैदा करती है। उक्त बातें श्री साधु ने शुक्रवार को होटल रेडिसन ब्लू में संवाददाताओं से बाचतीत में कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व-सीएसआर के खर्च को अनिवार्य कर दिया है। वित्त वर्ष 2015-16 में यह खर्च 913.73 करोड़ पहुंच गया। श्री साधु ने बताया कि आइआइएचएमआर विवि में दो वर्षीय रूरल मैनेजमेंट कोर्स के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरु गयी है। 30 जून तक ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

काबिल उम्मीदवारों में झारखंड दूसरे नंबर पर

जनगणना के अनुसार राज्य में 78,68,150 लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं। झारखंड आदिवासी विकास योजना, 2013 के अनुसार इनमें से 7.6 प्रतिशत के पास घरों में शौचालय और 2 प्रतिशत के घरों में जल निकासी की सुविधा है। हर 10 में से चार महिलाएं कुपोषित हैं। वहीं 18 से 29 वर्ष के उम्र के काबिल उम्मीदवारों में झारखंड देश में दूसरे नंबर पर है।